


Research Article

चंदौली जिले में मनरेगा की भूमिका: रोजगार सुरक्षा से ग्रामीण समृद्धि तक

Kumari Divya ^{1*}, Dr. Rashid Ali ²

¹ Research Scholar, Department of Commerce, KNIPSS, Sultanpur, Uttar Pradesh, India

² Associate Professor, Department of Commerce, KNIPSS, Sultanpur, Uttar Pradesh, India

Corresponding Author: *Kumari Divya

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17072213>

सारांश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करना और ग्रामीण विकास को गति देना है। यह शोध पत्र उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मनरेगा की भूमिका का विश्लेषण करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस योजना ने ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आय में स्थिरता, आजीविका सुरक्षा और पलायन पर नियंत्रण सुनिश्चित किया है। मनरेगा ने तालाब, नहर, सड़क और शौचालय जैसी अवसंरचनाओं के निर्माण से कृषि उत्पादकता और ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार किया है। साथ ही, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता, समान वेतन और सामाजिक निर्णयों में योगदान का अवसर प्रदान किया है। इस योजना ने न केवल गरीबी उन्मूलन और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया है, बल्कि ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि मजदूरी भुगतान में देरी और कार्य गुणवत्ता की चुनौतियाँ मौजूद हैं, परंतु पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर मनरेगा को ग्रामीण विकास का आदर्श मॉडल बनाया जा सकता है।

Manuscript Information

- ISSN No: 2583-7397
- Received: 15-07-2025
- Accepted: 26-08-2025
- Published: 07-09-2025
- IJCRM:4(5); 2025: 28-37
- ©2025, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

Divya K, Ali R. चंदौली जिले में मनरेगा की भूमिका: रोजगार सुरक्षा से ग्रामीण समृद्धि तक. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(5):28-37.

Access this Article Online


www.multiarticlesjournal.com

कुंजी शब्द: मनरेगा, चंदौली, रोजगार सुरक्षा, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण

परिचय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना विशेष रूप से उन ग्रामीण परिवारों के लिए है जो आजीविका के अवसरों के अभाव में आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं। मनरेगा न केवल रोजगार का साधन है, बल्कि यह ग्रामीण अवसंरचना, सामाजिक सशक्तिकरण और महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा देती है।

उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला, जो पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित है, सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से विविधता वाला जिला है। यहां पर कृषि मुख्य आजीविका का साधन है, किंतु भौगोलिक विषमताएं, छोटे भूखण्ड, सीमांत किसान, तथा सीमित औद्योगिक अवसर ग्रामीण जनजीवन को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में मनरेगा की भूमिका विशेष महत्व रखती है। यह शोध पत्र चंदौली जिले में मनरेगा की भूमिका का विश्लेषण करता है, और यह दर्शाता है कि कैसे रोजगार सुरक्षा से ग्रामीण समृद्धि की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं।

भौगोलिक एवं जनसांख्यिकी स्थिति

चंदौली जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और इसे पूर्वांचल क्षेत्र का प्रवेशद्वार भी कहा जाता है। यह जिला गाजीपुर, वाराणसी, बिहार के कैमूर, रोहतास और बक्सर जिलों से घिरा है। जिले का अधिकांश भाग गंगा नदी के मैदान में स्थित है, जहां उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो कृषि उत्पादन के लिए आदर्श है। जनसंख्या के हिसाब से जिले में 1428 गांव हैं, जिनमें से 34 प्रतिशत गांव छोटे हैं जिनकी जनसंख्या 500 से कम है। इन गांवों में कृषि भूमि छोटी होती है और अधिकांश परिवार मजदूरी या सहायक कार्यों पर निर्भर रहते हैं। लगभग 47 प्रतिशत गांव मध्यम आकार के हैं, जिनकी जनसंख्या 500 से 2000 के बीच है। इन गांवों में रोजगार और सामाजिक गतिविधियाँ अधिक होती हैं, साथ ही पंचायत भवन, स्वास्थ्य उपकेंद्र और शिक्षा सुविधाएँ मौजूद होती हैं। करीब 19 प्रतिशत गांव बड़े हैं, जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है। इन गांवों में कृषि के अलावा व्यापार और छोटे उद्योगों का भी विकास हुआ है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

चंदौली जिले में चकिया ब्लॉक सबसे बड़ा विकासखंड है, लेकिन यहाँ अधिकांश गांव छोटे आकार के हैं। इसका कारण यह है कि यह क्षेत्र वन और पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है, जहां आदिवासी और पारंपरिक समुदायों का वास है। बड़े गांवों की अनुपस्थिति के कारण यहां पर अवसंरचना का विकास धीमा है। इसके विपरीत नियामताबाद और सकलडीहा जैसे ब्लॉकों में बड़े गांवों की संख्या अधिक है, जिनकी भौगोलिक स्थिति समतल मैदानों वाली है और यहां की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है। यहां व्यापार और ग्रामीण उद्यमों का विकास हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर भी अधिक हैं।

नौगढ़ ब्लॉक की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। यह क्षेत्र आदिवासी और वनवासी समुदायों का घर है और यहां बड़े गांवों का अभाव है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र कठिन भू-भाग वाला है, जहां सड़क संपर्क सीमित है और आजीविका के अवसर कम हैं। इसके कारण यहां

विकास कार्यक्रमों की पहुंच भी सीमित है और महिलाएं मनरेगा जैसी योजनाओं में कम भागीदारी कर पाती हैं।

चंदौली जिले की जनसांख्यिकी स्थिति यह दिखाती है कि ग्रामीण विकास और रोजगार योजनाओं का प्रभाव हर क्षेत्र में समान नहीं हो सकता। जहां बड़े और मध्यम गांव हैं, वहां योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो सकती हैं, वहीं छोटे और दूरस्थ गांवों में इन योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। जिले की भौगोलिक विविधता और सामाजिक संरचना विकास के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं।

अवसंरचना की स्थिति

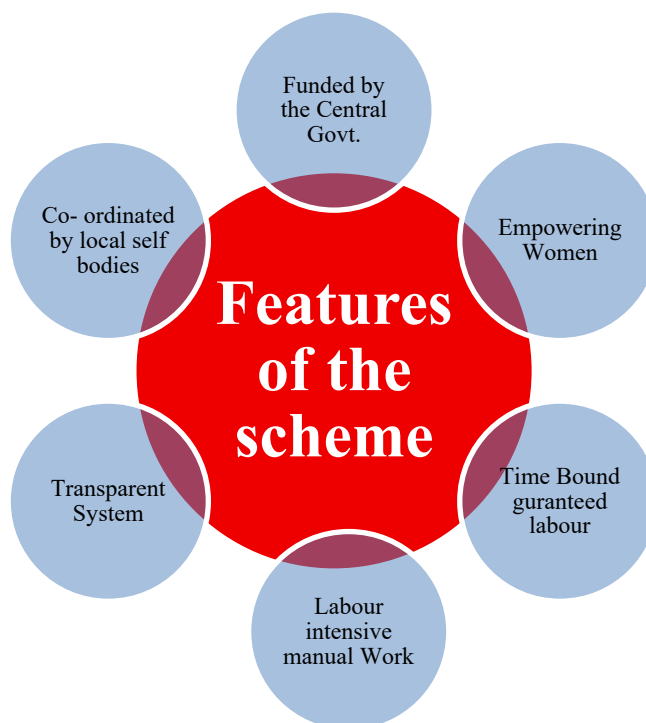
चंदौली जिले में 2023-24 तक कुल 734 ग्राम पंचायतें स्थापित की गई हैं, जिनमें से 615 पंचायत सचिवालय स्थापित हो चुके हैं और सभी पंचायतें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। इस उपलब्धि के साथ ही 702 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ है और 469 जनसेवा केंद्र सक्रिय हैं। पंचायत सचिवालय ग्रामीण प्रशासन के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि इंटरनेट कनेक्टिविटी ने सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच को सरल बना दिया है। इससे ग्रामीण जनता को सरकारी जानकारी और सेवाएँ समय पर मिल रही हैं। चंदौली में ई-गवर्नेंस को सशक्त बनाने के साथ-साथ, इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार क्षेत्रों में भी नई संभावनाएँ खुली हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 702 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण ने स्वच्छता को बेहतर बनाया है और खुले में शौच की समस्या को कम किया है। हालांकि, इन शौचालयों के नियमित रख-रखाव और उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि यह अधिक प्रभावी हो। जनसेवा केंद्रों ने ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर सरकारी सेवाएँ प्राप्त करने में मदद की है, जिससे उन्हें अब शहरों तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। इससे समय और धन की बचत हुई है और प्रशासनिक सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी है।

हालांकि, सामुदायिक केंद्रों की अनुपस्थिति अभी भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन केंद्रों का अभाव ग्रामीणों को सामूहिक बैठकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन में कठिनाई पैदा करता है। सामुदायिक केंद्रों के निर्माण से सामाजिक एकजुटता और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा, जो ग्राम स्तर पर विकास के पहलों को गति देगा।

अवसंरचना की वर्तमान स्थिति से यह स्पष्ट है कि चंदौली जिले ने प्रशासनिक और तकनीकी विकास की दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। पंचायत सचिवालयों की स्थापना, इंटरनेट कनेक्टिविटी और शौचालयों के निर्माण से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हुआ है। हालांकि, सामुदायिक केंद्रों की कमी को दूर करने की आवश्यकता है, ताकि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से संचालित हो सकें। भविष्य में, यदि पंचायत सचिवालयों का विस्तार सभी ग्राम पंचायतों तक हो, इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो, शौचालयों की नियमित देखभाल की व्यवस्था हो और सामुदायिक केंद्रों का निर्माण तेजी से किया जाए, तो चंदौली जिले की ग्रामीण अवसंरचना आदर्श मॉडल के रूप में उभर सकती है।

Figure 1: The Role of MGNREGA



मनरेगा का उद्देश्य

मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें न्यूनतम आजीविका सुरक्षा मिल सके। यह योजना ग्रामीण विकास कार्यों जैसे सड़क, तालाब, नहर, जल संरक्षण संरचनाओं तथा सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण से भी जुड़ी हुई है। चंदौली जैसे जिले में, जहां कृषि प्रमुख आजीविका का स्रोत है और औद्योगिक विकास सीमित है, मनरेगा ने ग्रामीणों को न केवल रोजगार दिया है, बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत आधार भी प्रदान किया है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिलता है, जिससे उनकी आय में निरंतरता बनी रहती है और वे बेरोजगारी या पलायन की समस्याओं से बच पाते हैं।

चंदौली जिले में मनरेगा के तहत जल संरक्षण, तालाबों और नहरों की मरम्मत, कच्ची सड़कों का निर्माण और सार्वजनिक सुविधाओं जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया गया है, जिससे न केवल रोजगार प्राप्त हुआ, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे का भी विकास हुआ। जल संरक्षण से कृषि उत्पादन में सुधार हुआ और सिंचाई की सुविधा बढ़ी। सड़क निर्माण से गाँवों को बेहतर तरीके से जोड़ा गया, जिससे बाजारों और शहरों तक पहुँच आसान हुई। मनरेगा ने महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। पहले जहाँ महिलाएँ घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, अब वे मनरेगा के अंतर्गत कार्य कर अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बढ़ा रही हैं। उन्हें समान मजदूरी मिल रही है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है।

मनरेगा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि श्रमिकों को उनकी मजदूरी सीधे बैंक खातों में मिलती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और पारदर्शिता बढ़ती है। यह व्यवस्था वित्तीय समावेशन को

बढ़ावा देती है और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त होता है। हालांकि, कुछ चुनौतियाँ जैसे मजदूरी भुगतान में देरी, कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान न देना और पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार हैं, जो योजना के सफल क्रियान्वयन में बाधक बनते हैं।

फिर भी, मनरेगा ने चंदौली जिले में ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। इस योजना ने न केवल रोजगार दिया, बल्कि बुनियादी ढांचे का विकास किया और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया। यदि कुछ सुधार किए जाएँ, तो यह योजना ग्रामीण विकास और सतत विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।

चंदौली में मनरेगा का प्रसार

चंदौली जैसे कृषि-प्रधान जिले में जहाँ औद्योगिक विकास सीमित है, मनरेगा ने रोजगार के अवसरों का महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान किया है। इस योजना ने विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के गाँवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहाँ कार्यबल की अधिकता और गैर-कृषि अवसरों की कमी है। मनरेगा ने यहाँ के ग्रामीणों को आय का वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आई और बेरोजगारी व पलायन की समस्या कम हुई। इस योजना के तहत श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार मिलता है, जिससे उनकी आय में निरंतरता बनी रहती है। विशेष रूप से उन परिवारों के लिए यह योजना लाभकारी है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और जो खेती पर निर्भर रहते हैं।

मनरेगा ने केवल रोजगार उपलब्ध नहीं कराया, बल्कि इसके अंतर्गत हुए कार्यों ने ग्रामीण अवसंरचना को भी मजबूत किया है। तालाब खुदाई, नहरों का सुधार, सड़क निर्माण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण से कृषि उत्पादन और सिंचाई की सुविधा बढ़ी

है, जिससे किसानों को दीर्घकालिक लाभ हुआ। सड़क निर्माण से ग्रामीणों को बाजार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में सुविधा हुई, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया।

महिलाओं के लिए भी मनरेगा एक महत्वपूर्ण साधन साबित हुआ है। पहले महिलाएँ घरेलू कार्यों तक सीमित रहती थीं, लेकिन अब वे इस योजना के तहत काम कर रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिली है और परिवार की आय में उनका योगदान सुनिश्चित हुआ है। महिलाओं को समान वेतन मिलने से लैंगिक समानता में भी सुधार हुआ है।

मनरेगा ने ग्रामीण पलायन की समस्या को भी नियंत्रित किया है। पहले, मजदूर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते थे, लेकिन अब वे अपने गाँवों में ही काम पा रहे हैं, जिससे पारिवारिक संरचना और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। इसके अलावा, इस योजना ने वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा दिया है क्योंकि श्रमिकों को सीधे बैंक खातों में मजदूरी मिल रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है।

हालाँकि, कुछ चुनौतियाँ भी हैं जैसे कार्यों की योजना का समय पर न बन पाना और मजदूरी भुगतान में देरी, लेकिन चंदौली में मनरेगा का प्रभाव व्यापक रूप से सकारात्मक रहा है। अगर कुछ सुधार किए जाएँ, जैसे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समुदाय की भागीदारी और तकनीकी साधनों का अधिकतम उपयोग, तो मनरेगा का प्रभाव और भी गहरा हो सकता है। यह योजना न केवल रोजगार गारंटी है, बल्कि ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण साधन भी है।

रोजगार सुरक्षा और आजीविका पर प्रभाव

मनरेगा ने चंदौली जिले में हजारों श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया है, जिससे उनकी आय में स्थिरता आई और ग्रामीण ऋणग्रस्तता कम हुई है। यह योजना विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ अधिकांश परिवार कृषि पर निर्भर होते हैं। मनरेगा ने उन्हें वैकल्पिक और स्थिर आय का स्रोत प्रदान किया, जिससे उनकी जीवन स्तर में सुधार हुआ। यह योजना न केवल रोजगार सुरक्षा देती है, बल्कि आय में स्थिरता भी सुनिश्चित करती है, जिससे परिवारों के बुनियादी खर्च जैसे भोजन, कपड़े, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा करना आसान हो गया है। इससे पहले जो परिवार ऋणग्रस्त थे, अब वे कर्ज से उबरने लगे हैं।

चंदौली में मनरेगा के तहत किए गए कार्यों ने श्रमिकों की आय बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण अवसंरचना में भी सुधार किया है। तालाब खुदाई, सड़क निर्माण, नहर मरम्मत और सार्वजनिक भवन निर्माण से गाँवों में स्थायी विकास की सुविधाएँ प्राप्त हुईं। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और किसानों की आय में सुधार हुआ। मनरेगा ने महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। पहले घरेलू कार्यों में सीमित महिलाएँ अब मनरेगा के कार्यों में भाग ले रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिली है। महिलाओं को समान वेतन मिलने से समाज में लैंगिक समानता भी बढ़ी है।

मनरेगा ने ग्रामीण पलायन की समस्या को भी कम किया है। पहले, श्रमिक रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन करते थे, लेकिन अब वे अपने गाँव में ही काम कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक जीवन और सामाजिक संरचना पर सकारात्मक असर पड़ा है। योजना

ने वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा दिया है, क्योंकि श्रमिकों को उनकी मजदूरी सीधे बैंक खातों में मिल रही है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है।

मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है। अब परिवार बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर पा रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ उठा पा रहे हैं। हालाँकि, समय पर मजदूरी का भुगतान और कार्य चयन में कुछ चुनौतियाँ हैं, लेकिन मनरेगा ने चंदौली के ग्रामीण श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। यदि इन चुनौतियों पर ध्यान दिया जाए, तो यह योजना और भी प्रभावी हो सकती है। यह केवल रोजगार गारंटी नहीं, बल्कि ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का एक ठोस साधन है।

गरीबी उन्मूलन में योगदान

मनरेगा ने चंदौली जिले में गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों को रोजगार मिलने से उनकी न्यूनतम जरूरतें पूरी होने लगी हैं, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ा है। पहले, ग्रामीण परिवारों को आय की स्थिरता नहीं होती थी, लेकिन मनरेगा ने उन्हें साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया, जिससे जीवन स्तर में सुधार हुआ। यह योजना केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नियमित आय से परिवार अब अधिक खर्च कर सकते हैं, जिससे भूख और कुपोषण में कमी आई है। मनरेगा से मिली आय ने बच्चों की शिक्षा में भी सुधार किया है। पहले, आर्थिक तंगी के कारण कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, लेकिन अब माता-पिता उन्हें स्कूल भेजने लगे हैं। यह शिक्षा का प्रसार गरीबी उन्मूलन का सबसे प्रभावी माध्यम बन गया है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि नियमित आय से परिवार अब छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज कर पा रहे हैं, और बच्चों को बेहतर आहार मिल रहा है।

इसके अतिरिक्त, मनरेगा ने सामाजिक दृष्टि से भी परिवर्तन लाया है। कई परिवार अब बिना कर्ज लिए अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और कुछ ने इस आय से छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, जैसे बकरी पालन और मुर्गी पालन। यह आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है।

चंदौली जैसे कृषि प्रधान जिले में मनरेगा ने बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया है। सड़कों, तालाबों, नहरों और कुओं के निर्माण से कृषि उत्पादन बढ़ा और किसानों की आय में दीर्घकालिक सुधार हुआ। सिंचाई सुविधाओं में सुधार ने फसलें सुरक्षित कीं और उत्पादन बढ़ाया।

महिलाओं के लिए भी मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले महिलाएँ घरेलू कार्यों तक ही सीमित रहती थीं, लेकिन अब उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिली है, जिससे उनके आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान में वृद्धि हुई है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा दिया है।

मनरेगा ने चंदौली में गरीबी उन्मूलन के लिए एक स्थायी मॉडल प्रस्तुत किया है, जो केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यदि इस योजना को पारदर्शिता

और दक्षता के साथ लागू किया जाए, तो यह आने वाले वर्षों में गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बना सकती है।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक प्रभाव

मनरेगा ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और न्यायसंगत रोजगार सुनिश्चित किया है, जिससे उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। चंदौली जिले के नियामताबाद, बरहनी, शाहाबगंज और सकलडीहा जैसे ब्लॉकों में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही है। इन क्षेत्रों में पंचायत सचिवालय, इंटरनेट सुविधा और जनसेवा केंद्र जैसी संस्थागत सुविधाएँ बेहतर हैं, जिसके कारण महिलाओं का पंजीकरण और भुगतान की प्रक्रिया सरल हुई है। महिलाओं को समय पर मजदूरी मिलती है और उन्हें भरोसा होता है कि उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अब पंचायत बैठकों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और स्थानीय विकास कार्यों में निर्णय ले रही हैं।

इसके विपरीत, नौगढ़ जैसे आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में महिला भागीदारी कम देखी गई है। इसका कारण सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताएँ, भौगोलिक दुर्गमता और अवसंरचना की कमी है। वहाँ महिलाएँ घर से बाहर जाकर मजदूरी करना सामाजिक रूप से उचित नहीं समझी जातीं, और वहाँ की खराब सड़कों और संचार सुविधाओं ने भी उनकी भागीदारी में रुकावट डाली है। हालांकि, इन बाधाओं के बावजूद यदि पंचायत सचिवालयों को सक्रिय किया जाए, मोबाइल बैंकिंग और महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जाए, तो महिला भागीदारी में वृद्धि हो सकती है।

मनरेगा ने महिलाओं को न केवल आर्थिक स्वतंत्रता दी है, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार किया है। पहले महिलाएँ घर की चारदीवारी तक सीमित थीं, लेकिन अब वे पंचायत बैठकों में अपनी राय दे रही हैं और परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग ले रही हैं। जब महिलाएँ स्वयं कमाने लगीं, तो उनके निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ी है। वे अब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार के अन्य खर्चों पर अपना प्रभाव डालने लगी हैं।

मनरेगा ने महिलाओं के लिए समान वेतन की भी व्यवस्था की है, जिससे लैंगिक भेदभाव कम हुआ है। अब महिलाओं को समान श्रम के लिए पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलती है, जो भारतीय ग्रामीण समाज में एक बड़ा परिवर्तन है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं में सामूहिकता और सहयोग की भावना भी विकसित हुई है, जिससे वे सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठा रही हैं। कई महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से छोटे व्यवसाय चला रही हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।

मनरेगा ने महिलाओं को न केवल श्रमिक बनाया है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त नागरिक बनने का अवसर भी दिया है। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन का एक प्रभावी साधन बन गई है, और इसके जरिए ग्रामीण समाज में सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है।

आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक पहचान

मनरेगा ने चंदौली जिले की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया है। पहले महिलाएँ घर की जरूरतों के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती थीं, लेकिन अब वे खुद मजदूरी अर्जित कर परिवार की आय में योगदान देने लगी हैं। इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ा और उन्होंने महसूस किया कि वे केवल परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाने वाली नहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक रीढ़ भी हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है, क्योंकि महिलाएँ अब अपनी कमाई से बच्चों की फीस, किताबें और अन्य खर्चों का प्रबंध करने लगी हैं। इससे न केवल बच्चों की शिक्षा में सुधार हुआ है, बल्कि परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का स्थायी साधन भी मिला है।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता ने बड़ा परिवर्तन किया है। पहले परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने पर महिलाओं और बच्चों की बीमारियों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन अब महिलाएँ बच्चों के टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में सक्रिय हो गई हैं। मनरेगा से मिली आय ने उन्हें स्वास्थ्य संबंधी फैसले लेने में सक्षम बनाया है।

सामाजिक स्थिति में सुधार का भी स्पष्ट असर हुआ है। महिलाएँ अब पंचायत बैठकों में भाग लेने लगी हैं और उनके विचारों को परिवार और समुदाय दोनों स्तरों पर महत्व मिलने लगा है। चंदौली जिले के कई ब्लॉकों में महिलाएँ विकास कार्यों, सड़क निर्माण, जल प्रबंधन और शिक्षा से जुड़े निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। मनरेगा से प्राप्त आय ने उन्हें निर्णयकर्ता बनने का अवसर दिया है। इसके अलावा, मनरेगा ने महिलाओं की सामाजिक पहचान को भी मजबूत किया है। पहले महिलाओं का श्रम अदृश्य रहता था, लेकिन अब उन्हें औपचारिक मजदूरी मिली है, जिससे उनके श्रम को सामाजिक मान्यता प्राप्त हुई है। महिलाएँ अब छोटे व्यवसायों में निवेश कर रही हैं और सामूहिक बचत समूहों से जुड़ रही हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय मिल रही है।

मनरेगा ने महिलाओं के भीतर लैंगिक समानता की नई चेतना जागृत की है। वे अब अपने अधिकारों और अवसरों को लेकर अधिक जागरूक हो गई हैं और कई जगहों पर वे बाल विवाह, दहेज और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने लगी हैं। हालांकि, कुछ स्थानों पर अभी भी चुनौतियाँ हैं, जैसे अवसंरचना की कमी और सामाजिक मान्यताएँ, लेकिन जहाँ महिलाओं को अनुकूल माहौल मिला है, वहाँ उनके जीवन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अंततः, मनरेगा ने महिलाओं को केवल आर्थिक स्वतंत्रता ही नहीं दी, बल्कि उन्हें परिवार और समाज के विकास में सक्रिय भागीदार बना दिया है। यह परिवर्तन एक स्थायी सामाजिक क्रांति की ओर संकेत करता है, जहाँ महिलाएँ अब केवल परिवार की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की भागीदार बन चुकी हैं।

ग्रामीण अवसंरचना और समृद्धि पर प्रभाव

मनरेगा के अंतर्गत चंदौली जिले में तालाब, नहर, सड़क और शौचालय जैसे निर्माण कार्यों ने ग्रामीण जीवन में दीर्घकालिक लाभ प्रदान किया है। जल संरक्षण संरचनाओं ने सिंचाई सुविधा बढ़ाई, जिससे किसानों की आय में सुधार हुआ। तालाबों का निर्माण और पुनर्जीवन जल संचयन में मददगार साबित हुआ, जिससे भूजल स्तर ऊँचा हुआ और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हुआ। नहरों का निर्माण भी कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक रहा, क्योंकि यह सस्ती और स्थायी सिंचाई सुविधा प्रदान करता है। अब किसान एक से ज्यादा फसलें ले पा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

सड़क निर्माण ने ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा। पक्की सड़कों के निर्माण से परिवहन की स्थिति बेहतर हुई, जिससे किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुँचाने में आसानी हुई। इसके अलावा, बच्चों के लिए स्कूल जाना और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँचना आसान हो गया। शौचालय निर्माण ने स्वच्छता में सुधार किया और "खुले में शौच मुक्त" अभियान को बढ़ावा दिया। इससे जलजनित रोगों में कमी आई और महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई।

इन निर्माण कार्यों ने न केवल बुनियादी सुविधाएँ प्रदान कीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति दी। तालाबों और नहरों ने कृषि उत्पादन बढ़ाया, जबकि सड़कों और शौचालयों ने सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया। इनसे मिलने वाला लाभ केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इनसे लाभान्वित होंगी।

मनरेगा के इन सार्वजनिक निर्माण कार्यों ने महिलाओं और कमजोर वर्गों को भी विशेष लाभ पहुँचाया। पानी की उपलब्धता बढ़ने से महिलाओं को पानी लाने की कठिनाई कम हुई, सड़कों ने उनकी आवाजाही को सुरक्षित और आसान बनाया, और शौचालयों ने उनकी गरिमा और स्वास्थ्य की रक्षा की। इन कार्यों ने ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया।

हालाँकि, कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य अधूरे रहे या गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया, फिर भी जहाँ कार्य सही तरीके से हुए, वहाँ ग्रामीणों को दीर्घकालिक लाभ मिला। यह साबित करता है कि यदि मनरेगा का संचालन निगरानी और पारदर्शिता के साथ हो, तो यह ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने में अत्यंत प्रभावी हो सकता है। मनरेगा ने न केवल रोजगार गारंटी दी है, बल्कि दीर्घकालिक ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता का भी सशक्त साधन साबित किया है।

डिजिटल और प्रशासनिक सुधार

मनरेगा ने चंदौली जिले में डिजिटल और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से गहरी पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाई है। जनसेवा केंद्रों (CSC) और इंटरनेट से जुड़ी पंचायतों ने इस योजना को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। पहले मजदूरी भुगतान नकद किया जाता था, जिससे भ्रष्टाचार और देरी की समस्याएँ थीं, लेकिन अब ऑनलाइन भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में किया जाता है, जिससे उन्हें समय पर भुगतान मिलता है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है।

जनसेवा केंद्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाएँ जैसे जॉब कार्ड पंजीकरण, मजदूरी स्थिति की जानकारी और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह केंद्र विशेष रूप से सहायक साबित हुए हैं, क्योंकि उन्हें अब बैंक या तहसील मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, इंटरनेट से जुड़ी पंचायतों ने प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा दिया है, जहाँ सभी कार्यों और भुगतानों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है। यह सुधार पारदर्शिता बढ़ाने और अधिकारियों के लिए निगरानी करना आसान बनाते हैं।

डिजिटल सुधारों का सबसे बड़ा लाभ कार्य आवंटन और निगरानी में देखा गया है। अब श्रमिकों को एसएमएस के माध्यम से कार्य की जानकारी दी जाती है और जियो-टैगिंग तकनीक के द्वारा यह सुनिश्चित

किया जाता है कि कार्य हुआ है या नहीं। इससे फर्जी काम दिखाकर पैसे निकालने की प्रवृत्ति पर रोक लगी है।

महिलाओं की भागीदारी में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि अब ऑनलाइन भुगतान उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में होता है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता मिलती है। इससे वे परिवार के निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना इन सुधारों की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। पहले मजदूरी भुगतान में देरी आम बात थी, लेकिन अब ऑनलाइन प्रणाली ने इस समस्या को काफी हद तक समाप्त कर दिया है। शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत किया गया है, जिससे श्रमिकों को त्वरित समाधान मिलता है।

हालाँकि, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता जैसी कुछ चुनौतियाँ हैं, लेकिन इन सुधारों ने मनरेगा को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बना दिया है। यदि इन सुधारों को और अधिक व्यापक बनाया जाए और डिजिटल सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए, तो मनरेगा न केवल रोजगार गारंटी बल्कि ग्रामीण भारत की प्रशासनिक क्रांति का भी उदाहरण बन सकता है।

चंदौली जिले में मनरेगा का डाटा विश्लेषण

चंदौली जिला उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कृषि प्रधान जिला है, जहाँ आजीविका का मुख्य साधन कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियाँ हैं। जिले की सामाजिक-आर्थिक संरचना, जनसंख्या का वितरण तथा ग्रामीण अवसंरचना की स्थिति, मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के प्रभाव का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रस्तुत अध्याय में जनसांख्यिकीय, अवसंरचनात्मक तथा मनरेगा से संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

जनसांख्यिकीय परिदृश्य

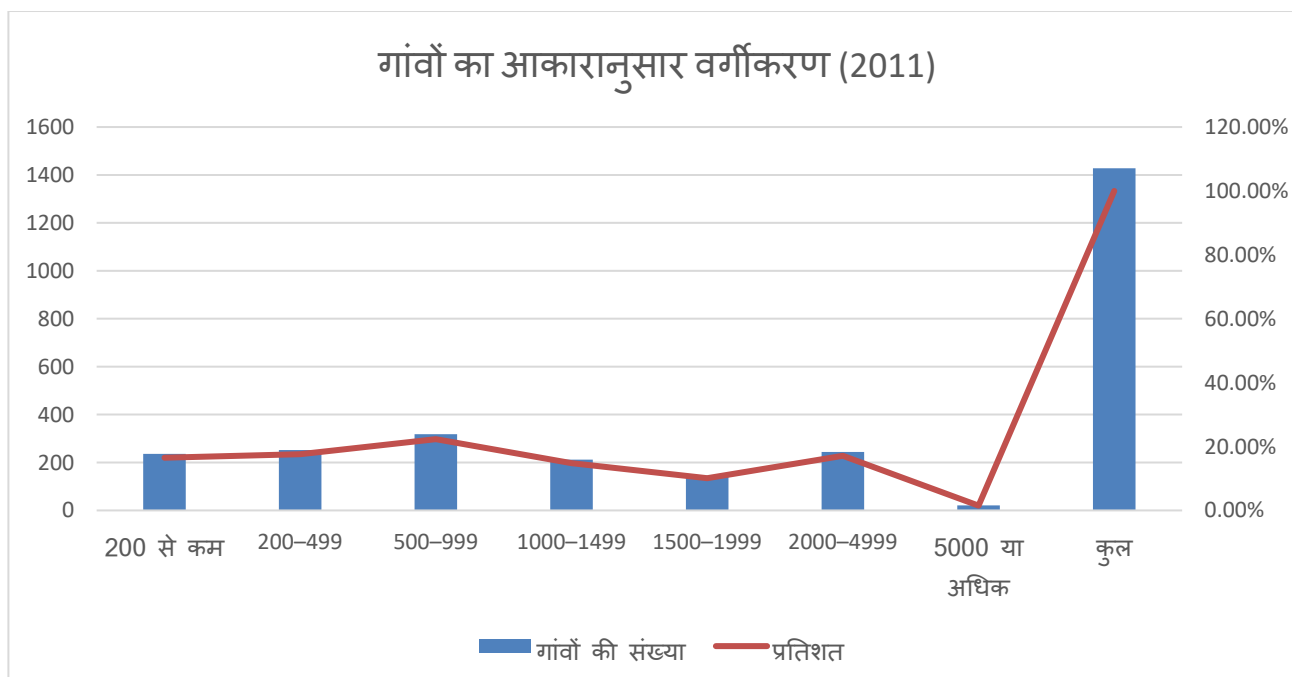
जनसांख्यिकीय परिदृश्य के अनुसार, चंदौली जिले में कुल 1627 गांव हैं, जिनका आकार असमान है। जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार, 16.5% गांवों की जनसंख्या 200 से कम है, जबकि 17.6% गांवों की जनसंख्या 200 से 499 तक है। 22.3% गांवों की जनसंख्या 500 से 999 के बीच है, जो जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 14.8% गांवों में जनसंख्या 1000 से 1499 के बीच है, और 10.1% गांवों की जनसंख्या 1500 से 1999 तक है। 17.1% गांवों में जनसंख्या 2000 से 4999 तक है, जबकि केवल 1.5% गांवों की जनसंख्या 5000 या उससे अधिक है।

इन आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि जिले में अधिकांश गांव मध्यम आकार के हैं, जिनकी जनसंख्या 500 से 1000 के बीच है। वहीं, 2000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों की संख्या कम है। छोटे गांवों की अधिकता इस बात का संकेत देती है कि जिले की बड़ी आबादी छोटे और कम आबादी वाले गांवों में बसी हुई है। इस तरह की जनसांख्यिकीय संरचना विकास योजनाओं की प्राथमिकताओं और ग्रामीण विकास में विभिन्न चुनौतियों को दर्शाती है।

तालिका: 1 जनगणना 2011 के अनुसार चंदौली जिले में कुल 1627 गांव हैं। गांवों का आकार असमान है, जिनमें छोटे, मध्यम और बड़े गांव सम्मिलित हैं।

जनसंख्या श्रेणी	गांवों की संख्या	प्रतिशत
200 से कम	236	16.5%
200-499	252	17.6%
500-999	318	22.3%
1000-1499	212	14.8%
1500-1999	145	10.1%
2000-4999	244	17.1%
5000 या अधिक	21	1.5%
कुल	1627	100%

Figure: 2 गांवों का आकारानुसार वर्गीकरण (2011)



विकासखण्डवार गांवों और पंचायतों का वितरण

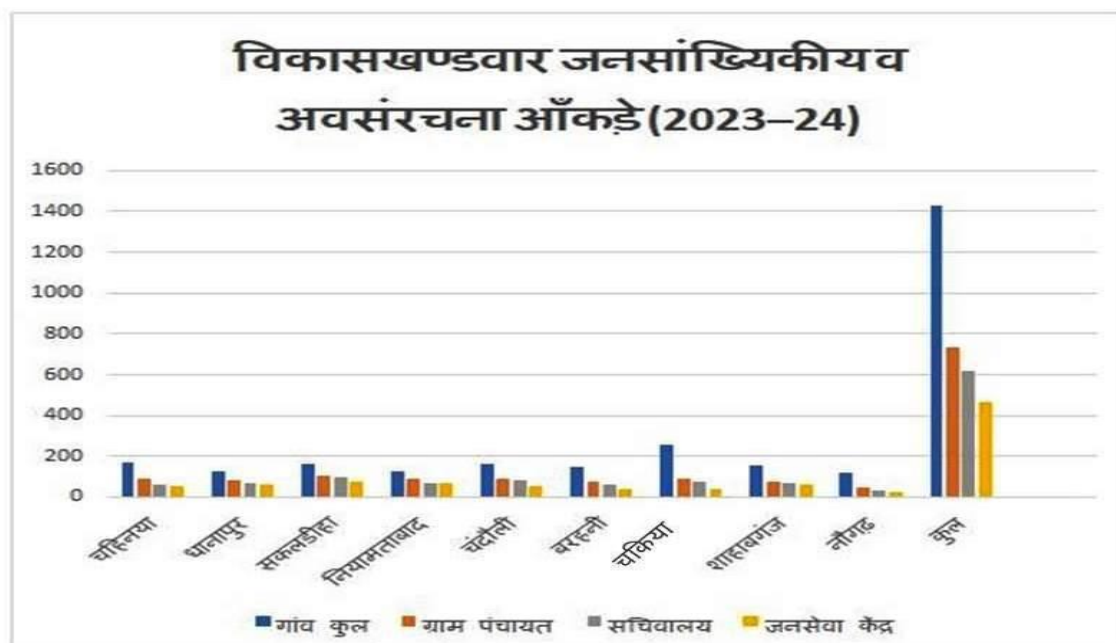
चहनिया विकासखण्ड में कुल 167 गांव हैं, जिनमें 91 ग्राम पंचायतें और 64 पंचायत सचिवालय स्थापित हैं। यहाँ 51 जनसेवा केंद्र सक्रिय हैं। धानापुर में 124 गांव हैं, 84 ग्राम पंचायतें और 67 सचिवालय हैं, जबकि 61 जनसेवा केंद्र कार्यरत हैं। सकलडीहा में 165 गांव हैं और 104 ग्राम पंचायतों के साथ 98 सचिवालय स्थापित हैं, जहाँ 73 जनसेवा केंद्र हैं। नियामताबाद में 124 गांव हैं, 88 ग्राम पंचायतें और 66 सचिवालय हैं, और 68 जनसेवा केंद्र सक्रिय हैं। चंदौली विकासखण्ड में 165 गांव हैं, 88 ग्राम पंचायतें और 81 सचिवालय स्थापित हैं, जबकि 53 जनसेवा केंद्र हैं। बरहनी में 149 गांव हैं, 75 ग्राम पंचायतें और 63

सचिवालय हैं, और 40 जनसेवा केंद्र हैं। चकिया में 258 गांव हैं, 89 ग्राम पंचायतें और 72 सचिवालय हैं, जबकि 40 जनसेवा केंद्र कार्यरत हैं। शाहाबगंज में 155 गांव हैं, 72 ग्राम पंचायतें और 70 सचिवालय हैं, और 58 जनसेवा केंद्र हैं। नौगढ़ में 121 गांव हैं, 43 ग्राम पंचायतें और 34 सचिवालय हैं, और 25 जनसेवा केंद्र हैं। कुल मिलाकर, जिले में 1627 गांव हैं, 734 ग्राम पंचायतें और 615 सचिवालय स्थापित हैं, साथ ही 469 जनसेवा केंद्र सक्रिय हैं। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि जिले में बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हो रहा है, जिससे ग्रामीणों को बेहतर प्रशासनिक और सरकारी सेवाएँ उपलब्ध हो रही हैं।

तालिका 2: विकासखण्डवार जनसांख्यिकीय व अवसंरचना आँकड़े (2023-24)

विकासखण्ड	गांव कुल	ग्राम पंचायत	सचिवालय	जनसेवा केंद्र
चहनिया	167	91	64	51
धानापुर	124	84	67	61
सकलडीहा	165	104	98	73
नियामताबाद	124	88	66	68
चंदौली	165	88	81	53
बरहनी	149	75	63	40
चकिया	258	89	72	40
शाहाबगंज	155	72	70	58
नौगढ़	121	43	34	25
कुल	1627	734	615	469

Figure: 3 विकासखण्डवार जनसांख्यिकीय व अवसंरचना आँकड़े (2023-24)



अवसंरचना विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी

चंदौली जिले की सभी ग्राम पंचायतें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। 615 पंचायत सचिवालय स्थापित किए जा चुके हैं। 702 सामुदायिक शौचालय निर्मित किए गए हैं। हालांकि सामुदायिक केंद्रों का अभाव अब भी सामुदायिक गतिविधियों को सीमित करता है। डिजिटल सुधारों से मजदूरी भुगतान अब सीधे बैंक खातों में होता है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ा है। जनसेवा केंद्रों ने ग्रामीणों के लिए सेवाएँ सरल की हैं।

मनरेगा के अंतर्गत रोजगार और आजीविका

मनरेगा ने ग्रामीण श्रमिकों को कृषि कार्यों के अतिरिक्त समय में रोजगार उपलब्ध कराया।

- हजारों श्रमिकों को वर्ष में 100 दिन का काम सुनिश्चित हुआ।
- पलायन की समस्या कम हुई और परिवार की आय स्थिर हुई।
- महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक पहचान मजबूत हुई।

गरीबी उन्मूलन और सामाजिक प्रभाव

- छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों की आय बढ़ी।
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि हुई।
- ऋणग्रस्तता में कमी आई।
- महिलाओं की पंचायत बैठकों में भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में उपस्थिति बढ़ी।

सार्वजनिक निर्माण कार्य

मनरेगा के अंतर्गत चंदौली जिले में तालाब, नहर, सड़क और शौचालय जैसे कार्य हुए।

- **तालाब और नहरें:** सिंचाई सुविधाओं में सुधार।
- **सड़क निर्माण:** परिवहन व बाजार तक पहुँच आसान हुई।
- **शौचालय:** स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

- भुगतान में देरी, जिससे श्रमिकों में असंतोष।
- नौगढ़ जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में कम महिला भागीदारी और कमजोर अवसंरचना।
- कुछ स्थानों पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं।
- जातीय और लैंगिक असमानताएँ योजना के सफल क्रियान्वयन में बाधा।

निष्कर्ष

डाटा विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा ने चंदौली जिले के ग्रामीण जीवन में गहरा प्रभाव डाला है। इस योजना ने रोजगार और आय स्थिरता में वृद्धि की है, गरीबी को कम किया है और शिक्षा-स्वास्थ्य पर निवेश बढ़ा है। महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को भी बल मिला है, जिससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण अवसंरचना और डिजिटल सुधारों ने विकास की नींव को मजबूत किया है। हालांकि, कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जैसे कि भुगतान में देरी, दूरस्थ क्षेत्रों में अवसंरचना की कमी और सामाजिक विषमताएँ। इन चुनौतियों का समाधान होने पर, चंदौली जिला मनरेगा के क्रियान्वयन का एक आदर्श मॉडल बन सकता है।

चंदौली जिले में मनरेगा की भूमिका बहुआयामी है। यह केवल रोजगार सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण विकास, अवसंरचना निर्माण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय का भी साधन बन चुका है। हालांकि भौगोलिक विषमता, सामाजिक मान्यताएँ और कार्यों की मौसमी प्रकृति जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, फिर भी इसका समग्र प्रभाव ग्रामीण समृद्धि की ओर अग्रसर है। चंदौली का अनुभव यह दर्शाता है कि यदि योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जाए, पंचायत स्तर पर अवसंरचना को मजबूत किया जाए और महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाए, तो मनरेगा न केवल रोजगार सुरक्षा बल्कि समग्र ग्रामीण समृद्धि का एक सशक्त माध्यम बन सकता है।

संदर्भ

1. चौहान के, बाला ए. हिमालयी राज्यों में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार की गतिशीलता: हिमाचल प्रदेश का एक अध्ययन. *Int J Soc Sci Res (IJSSR)*. 2025;2(3):352-66.
2. दत्ता बी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का ग्रामीण आजीविका पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: पश्चिम बंगाल के कूच बिहार ज़िले का एक अध्ययन [डॉक्टरल शोध प्रबंध]. उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय; 2021.
3. यादव एस. पूर्वी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार अवसरों की पहली. *Interdiscip Inst Human Security Govern*. 2024.
4. पंकज ए. सामाजिक सशक्तिकरण: एक अनपेक्षित परिणाम. In: समावेशी विकास गारंटीकृत रोजगार के माध्यम से: भारत के मनरेगा अनुभव. सिंगापुर: Springer Nature Singapore; 2022. p.147-70.
5. पटेल एस, मल्ल आरके, चतुर्वेदी ए, सिंह आर, चंद आर. भारतीय किसानों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति निष्क्रिय अनुकूलन. *Ecol Indic*. 2023;154:110637.
6. कुमार एम. उत्तर प्रदेश के बाँदा ज़िले में मनरेगा के प्रभाव पर एक अध्ययन [डॉक्टरल शोध प्रबंध]. बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय; 2021.
7. शिवा एल. भगवान शिव, माता-पिता और शिक्षकों को समर्पित [डॉक्टरल शोध प्रबंध]. सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय; 2023.
8. चौरा टी, हिक्स डी. काम करने और जीने का अधिकार: भारत के मनरेगा कार्यक्रम के गुमशुदा महिलाओं पर निहितार्थ. *Soc Sci Q*. 2021;102(6):2528-51.
9. केशरवानी एस. नक्सलवाद और कानून: छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में. *Indian J Integr Res Law*. 2023;3:1.
10. चौरा टी. विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक सुधार. 2021.
11. जमाल एस, उपाध्याय ए, दुआ आर. सात समुद्र पार: कोविड-19 से उत्पन्न प्रवासी संकट उत्तर प्रदेश के संदर्भ में. *Sustain Agric Food Environ Res*. 2023;12(1).
12. जमाल एस, उपाध्याय ए, दुआ आर. Cruzando los siete mares: Covid 19 indujo la crisis migratoria con referencia a Uttar Pradesh.
13. वीर एससी. मातृ एवं शिशु कुपोषण: कार्यक्रम, अनुभव और वर्तमान फोकस. In: *Child, Adolescent and Woman Nutrition in India*. Routledge; 2023. p.170-247.
14. कुनीहरो ए, थापन एम. समकालीन भारत में उपalternity, हाशियाकरण और एजेंसी. 2022.
15. सिंह आरपी. प्रोफेसर रवि एस. सिंह (1971~2021): विरासत और स्मारक. *Space Cult India*. 2021;9(1):149-56.
16. गिरी एके, सिंह एसपी. भारत का हाथ-बुना कालीन उद्योग: उदारीकरण के बाद का दौर, निर्यात प्रदर्शन और चुनौतियाँ. In: *State and Capitalist Development in India*. Routledge; 2023. p.206-30.
17. शर्मा एस, कुमार पी. मनरेगा का ग्रामीण रोजगार और अवसंरचना विकास पर प्रभाव: भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का एक केस अध्ययन. *J Rural Dev*. 2022;41(4):522-37.
18. देशमुख आर, पांडे पी. सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार: उत्तर प्रदेश में मनरेगा की भूमिका का अध्ययन. *Econ Polit Wkly*. 2020;55(22):45-60.
19. गुप्ता ए, सिंह वी. ग्रामीण विकास और शासन: भारत में मनरेगा की भूमिका का विश्लेषण. *Indian J Public Adm*. 2021;67(3):108-24.
20. बंसल ए, सैनी आर. मनरेगा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण: राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से साक्ष्य. *Int J Gender Stud*. 2022;33(1):67-79.
21. कुमार आर, गुप्ता के. मनरेगा और ग्रामीण अवसंरचना पर इसका प्रभाव: छत्तीसगढ़ का एक केस अध्ययन. *J Rural Econ*. 2020;39(2):241-58.

22. मेहता एस, रानी एम. रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय: भारत में मनरेगा की आलोचनात्मक समीक्षा. Int Rev Public Policy. 2023;12(1):37-50.
23. सिंह एच, राज एन. मनरेगा का गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास में योगदान का मूल्यांकन. Asian J Rural Dev. 2021;5(3):99-112.
24. शर्मा ए, मिश्रा पी. मनरेगा का ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव. J Women Stud. 2022;41(2):84-99.
25. पटेल जे, यादव आर. मनरेगा और सतत ग्रामीण विकास: बिहार का एक केस अध्ययन. J Dev Stud. 2020;45(3):202-14.
26. खन्ना वी, जोशी एन. मनरेगा: ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का एक उपकरण. J Financ Inclus. 2021;8(4):93-108. पत्रिका, 8(4), 93-108।

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

About the Corresponding Author



कुमारी दिव्या वाणिज्य विभाग, के.एन.आई.पी.एस.एस., सुलतानपुर की शोधार्थी हैं, जो डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से संबद्ध हैं। उनका शोध क्षेत्र वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन से संबंधित है।